अबू सालेम अब्दुल कयूम अन्सारी

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 415-416/2012)

5 अगस्त, 2013।

[पी. सतशिवम, सीजेआई और जे. चेलामेश्वर, जे.)

विकिरण अधिनियम, 1962:

एसएस 3(1) और 21-प्रत्यर्पण-1993 के बॉम्बे विस्फोट मामले में अभियुक्त, पुर्तगाल से भारत को इस आश्वासन पर प्रत्यर्पित किया गया कि उसे 25 साल से अधिक की मौत की सजा और कारावास नहीं दिया जाएगा-अतिरिक्त आरोप बनाए गए-अतिरिक्त आरोपों के लिए अभियुक्तों के मुकदमे के संबंध में भारत की अदालतों और पुर्तगाल की अदालतों के बीच राय का अंतर-सी. बी. आई. ने अबू सलेम में फैसले को संशोधित आदेशने की मांग की और अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने के लिए प्रार्थना की-आयोजितः1इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता को भारत में प्रत्यर्पित किया गया था, वे उसे अधिकतम सजा देने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं और इसलिए, यदि संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है तो कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा-तदनुसार, सी. बी. आई. की प्रार्थना की अनुमति दी गई और अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने की अनुमति दी गई-हालाँकि, अबू सलेम के निर्णय में दिए गए विश्लेषण और तर्क विशेषता के सिद्धांत की व्याख्या के संबंध में भारत के संविधान के ध्यान दें 141 के तहत न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में अच्छा है और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा-भारत का संविधान, 1950-ध्यान दें 141

एसएस 3(1) और 21-1993 के बॉम्बे विस्फोट मामले में अभियुक्तों के प्रत्यर्पण की अनुमति देने वाला पुर्तगाल सरकार का मंत्रिस्तरीय आदेश-विशेष न्यायालय द्वारा बनाए गए अतिरिक्त आरोप-लिस्बन अपील न्यायालय ने प्रत्यर्पण आदेश के उल्लंघन में अतिरिक्त आरोप लगाए और दिए गए प्राधिकरण को समाप्त किया जाना चाहिए-आयोजित किया गयाःपुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पुर्तगाली कानून 'विशिष्टता के सिद्धांत' के उल्लंघन के लिए किसी विशिष्ट परिणाम का प्रावधान नहीं करता है और निष्कर्षों को भारत संघ को अपीलकर्ता को पुर्तगाल को वापस करने के निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह केवल पुर्तगाल सरकार के लिए एक कानूनी आधार के रूप में काम करेगा, यदि वह राजनीतिक, या राजनयिक माध्यमों द्वारा से अपीलकर्ता की पुर्तगाल में वापसी की मांग करने का विकल्प चुनती है, जो आज तक नहीं किया गया है-मामले के इस दृष्टिकोण में, दिनांकित 'आईडी1' प्रत्यर्पण का आदेश कानून की नजर में वैध और प्रभावी है।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 136-भारत का सर्वोच्च न्यायालय-अपने निर्णयों को संशोधित करने की शक्ति आयोजितः भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायाधीशालय को अपने पहले के निर्णय को संशोधित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है यदि वह पाता है कि संशोधन याचिका में बताई गई त्रुटि गलती से हुई थी और पहले का निर्णय गलत धारणा के लिए पारित नहीं किया गया होता, जो वास्तव में मौजूद नहीं था और इसके अपराध के परिणामस्वरूप न्यायाधीश का गर्भपात हुआ था-अंतर्वर्ती आवेदन।

आंतरिक त्रिकोणीय कानूनः

प्रत्यर्पण-समझाया गया।

अपीलकर्ता टाडा विशेष मामला सं. 189 में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक था। 1-1993 का बी और 2006 का विशेष मामला संख्या 1 टाडा के तहत नामित अदालत के समक्ष 12.3.1993 पर मुंबई में सिलसिलेवार बम हमले करने के लिए। नामित न्यायालय ने टाडा की धारा 3 (3) के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का एक सामान्य आरोप तैयार किया। दंड संहिता, 1860, शस्त्र अधिनियम, 1959, विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 के तहत कई अन्य आरोप भी बनाए गए थे। चूंकि अपीलकर्ता फरार हो गया था, इसलिए इंटरपोल द्वारा से एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जिसके कारण लिस्बन में पुर्तगाली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। भारत सरकार ने 9 आपराधिक मामलों में अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया और पुर्तगाल सरकार को आश्वासन दिया कि यदि अपीलकर्ता को भारत में मुकदमे के लिए प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे न तो मौत की सजा दी जाएगी और न ही 25 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। भा.दं.सं.विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और एस. एस.4 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984। आई. डी. 1 पर, अपीलकर्ता को भारत लाया गया और आर. सी.-1 (एस/93)/सी. बी. एल./एस. टी. एफ., यानी 1993 के बी. बी. सी. नंबर 1 में नामित न्यायालय, मुंबई के समक्ष पेश किया गया।

आई. डी. 1 पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 (8) के तहत एक पूरक आरोप पत्र 1993 के बी. बी. सी. संख्या 1 में नामित न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के संबंध में दायर किया गया था। दिनांक 18.03.2006 के आदेश के अनुसार, मूल शुल्क, इसके अलावा। अपीलकर्ता के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था। दिनांक 13.06.2006 के आदेश द्वारा, नामित न्यायालय ने मुकदमे को अलग करने के लिए आवेदन की अनुमति दी और कहा कि मुकदमा 1993 के बीबीसी-1 बी के

रूप में जारी रहेगा, जिसमें पहले का संयुक्त मामला 1993 का बीबीसी नंबर 1 था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आश्वासन उस सजा के संबंध में दिए गए थे जिसे अधिरोपित किया जा सकता था न कि उन अपराधों के संबंध में जिनके साथ उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था। उक्त आदेश को 2006 दाण्डिक अपीलीय सं 990 और 2006 की रिट याचिका संख्या 171 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्पण डिक्री के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी।

अपीलकर्ता ने लिस्बन अपील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया जिसमें कहा गया कि उन पर भारत में 99 के कानून 144 के अनुच्छेद 16 में निहित विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए मुकदमा चलाया जा रहा है। अपील न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा मामले को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 दाण्डिक अपीलीय सं 990 के साथ-साथ 2006 की रिट याचिका संख्या 171 में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अबू सलेम1 में दिनांक 1 के फैसले द्वारा अपील के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। लिस्बन न्यायालय। अपील, दिनांक 14.09.2011 के निर्णय द्वारा, अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण के लिए दिए गए प्राधिकरण को समाप्त किया जाना चाहिए। पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने भारत संघ की अपील को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया, हालांकि, पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायाधीशालय ने 05.07.2012 पर भारत संघ द्वारा दायर अपील का फैसला करते हुए कहा कि नए अपराधों के मुकदमे को अवैध मानने और अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण के लिए दिए गए प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लेने के बावजूद, लिस्बन अपील न्यायाधीशालय का निर्णय केवल विशेषज्ञता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए समाप्त होता है। यह अपने आप में अनुरोध करने वाले राज्य को किसी निश्चित कार्य के अभ्यास और प्रत्यर्पित व्यक्ति को वापस करने के लिए

बाध्य नहीं करता है और इस प्रकार यह भारत संघ के खिलाफ दिया गया निर्णय नहीं है, एक ऐसा निर्णय जो प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से इसे पूर्वाग्रहित करता है।

इसके बाद अपीलकर्ता ने विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किए, जिसने उन्हें खारिज कर दिया। अपीलकर्ताकर्ता ने अपील दायर की। अपीलों के निपटारे तक, प्रतिवादी-सी. बी. आई. ने सी. आर. एल. दायर किया। विविध। 2013 की याचिका संख्या 3301-3302 में अबू सलेम में दिनांकित 10.09.2010 के फैसले के स्पष्टीकरण/संशोधन के साथ-साथ दिनांकित 18.3.2006 के स्थगन आदेश द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप (iii) से (viii) को वापस लेने की अनुमति और दिनांकित 17.02.2012 के स्थगन स्थगन आदेश को हटाने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थेः(i) क्या न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए आधारों के तहत अबू सलेम में दिए गए निर्णय को संशोधित कर सकता है; और (ii) क्या अपीलकर्ता द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार दिनांकित प्रत्यर्पण का आदेश रद्द/रद्द कर दिया गया था।

अपीलों और सी. आर. एल. का निपटारा किया अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायाधीशालय को अपने पहले के फैसलों पर पुनर्विचार, संशोधन और संशोधन करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है क्योंकि कानून को न्यायाधीश के सामने झुकना पड़ता है। निश्चित रूप से, इस न्यायाधीशालय को त्रुटि को सुधारने से कुछ भी नहीं रोक सकता है यदि वह पाता कि संशोधन याचिका में बताई गई त्रुटि गलती से हुई थी और पहले का निर्णय गलत धारणा के लिए पारित नहीं किया गया होता जो वास्तव में मौजूद नहीं था और इसके अपराध के परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता हुई थी। [पैरा 11] [1081-डी-ई] डी

1.2 दिए गए मामले में, एकमात्र आधार जिस पर प्रत्यर्थी/सी. बी. आई. संशोधन चाहता है, वह है भारतीय न्यायालयों और पुर्तगाल में न्यायालयों द्वारा विशेषज्ञता के सिद्धांत के उल्लंघन के संबंध में व्यक्त किए गए अलग-अलग विचारों से उत्पन्न स्थिति को सुसंगत बनाना, और तदनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने की अनुमति मांगना [पैरा 12] [1081-एफ; 1082-बी-सी]

1.3 प्रत्यर्पण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें एक संप्रभु दूसरे संप्रभु को आत्मसमर्पण करता है-एक अभियुक्त, अपराधी या भगोड़े अपराधी के रूप में वांछित व्यक्ति-अनुरोध करने वाले संप्रभु को व्यक्तियों की यह डिलीवरी आमतौर पर संधियों या द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित होती है, लेकिन कभी-कभी यह संप्रभुों के बीच शिष्टाचार और सद्भावना के मामले के रूप में पारस्परिकता और सौहार्द से भी होता है, जैसा कि तत्काल मामले में होता है। इसलिए, 'विश्व सार्वजनिक व्यवस्था' आवर्ती विषय है जिसके आधार पर राज्यों द्वारा प्रत्यर्पण का अभ्यास किया जाता है। [पैरा 13] [1082-सी-ई]

1.4 इस तथ्य पर ध्यान दें हुए कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता को भारत प्रत्यर्पित किया गया था, वे अपीलकर्ता को अधिकतम सजा देने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं और इसलिए, यदि संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, इस न्यायालय का विचार है कि मौजूदा विशिष्ट परिस्थितियों में संशोधन याचिका को अनुमति देना किसी भी पक्ष के लिए हानिकारक नहीं होगा। हालाँकि, यह स्पष्ट करना उचित है कि प्रतिवादी द्वारा दायर संशोधन याचिका को अनुमति देकर, यह नहीं माना जा सकता है कि यह न्यायालय पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय के फैसले के आलोक में फैसले की समीक्षा कर रहा है। भारत और पुर्तगाल दोनों कुशल और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली वाले दो संप्रभु राज्य हैं। परिणामस्वरूप, स्पष्ट शब्दों में, पुर्तगाल

के संवैधानिक न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इसका केवल प्रेरक मूल्य है। [पैरा 14] [1082-एफ-एच; 1083-ए]

1.5 नतीजतन, हालांकि इस महान्यायवादी ने अदालतों के हित में और महान्यायवादी द्वारा दिए गए इस बयान पर कि मामले को राजनयिक माध्यमों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, सी. बी. आई. को संशोधन याचिका की अनुमति देते हुए अतिरिक्त आरोप-पत्र में आरोप (iii) द्वारा (viii) को वापस लेने की अनुमति दी गई है, सी. बी. आई. के पक्ष में निर्णय दिया है। महान्यायवादी ने इस न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि वे महान्यायवादी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में लंबित अन्य आरोपों को भी वापस लेने की प्रक्रिया में हैं, जिनके प्रत्यर्पण आदेश का उल्लंघन करने का दावा किया जाता है। [पैरा 15] [1083-बी-डी]

1.6 फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधन याचिका की अनुमति केवल अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने की सीमा तक ही दी जाती है। तथापि, विशिष्टता के सिद्धांत की व्याख्या के संबंध में निर्णय में दिया गया विश्लेषण और तर्क अभी भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में अच्छा है और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। [पैरा 16) [1083-डी-ई]

2.1 जहां तक दिनांक 1 के प्रत्यर्पण आदेश की स्थिति का संबंध है, पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय ने स्पष्ट रूप द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि पुर्तगाली कानून विशिष्टता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए किसी विशिष्ट परिणाम का प्रावधान नहीं करता है और उनके निष्कर्षों को भारत संघ को अपीलकर्ता को पुर्तगाल वापस करने के निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह केवल पुर्तगाल सरकार के लिए एक कानूनी आधार के रूप में काम करेगा, यदि वह राजनीतिक या राजनयिक माध्यमों

द्वारा अपीलकर्ता को पुर्तगाल वापस करने का अनुरोध करने का विकल्प चुनती है, जो आज तक नहीं किया गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, दिनांकित प्रत्यर्पण का आदेश 28.03.2003 कानून की नजर में वैध और प्रभावी है। [पैरा 17) [1083-एफ, जी-एच; 1084-ए-बी] डी

2.2 परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी-सी. बी. आई. को अतिरिक्त शुल्कों की संख्या (iii) से (viii) तक शुल्क वापस लेने की अनुमति है। नतीजतन, 17.02.2012 दिनांकित स्थगन स्थगन आदेश को खाली कर दिया जाता है और मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी जाती है। [पैरा 18) [1084-सी-डी]

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः दाण्डिक अपीलीय सं. 415-416/2012

1993 के टाडा विशेष मामला संख्या 1-बी में प्रदर्शनी संख्या 208 और 2006 के टाडा विशेष मामला संख्या 1 में प्रदर्शनी संख्या 491 में ग्रेटर बॉम्बे के लिए मुंबई में नामित न्यायाधीश (टाडा का नामित न्यायालय) के दिनांकित 08.11.2011 निर्णय और आदेश से।

जी. ई. वाहनवती, एजी, सिद्धार्थ लूथरा, एएसजी, सुदीप पासबोला, शोभा कुर्शी, सुशील करंजकर, के. एन. राय, मोहम्मद। उपस्थित दलों के लिए निजाम पाशा, सुप्रिया जुनेजा, बैराम दास, अर्जुन दीवान, अरविंद कुमार शर्मा, आशा जी. नायर, संजय खारदे।

न्यायालय का निर्णय ए. पी. सतशिवम, सीजेआई द्वारा दिया गया था।

1. ये अपील, अपीलकर्ता-अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी के कहने पर, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'टाडा') की खंड 19 के तहत दायर की गई हैं, जिसमें 1993 के टाडा विशेष मामले संख्या 1-बी और 2006 के विशेष मामले संख्या 1 में बॉम्बे बम विस्फोट मामले, ग्रेटर बॉम्बे के लिए टाडा के तहत नामित अदालत द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश को

चुनौती दी गई है, जिसमें नामित न्यायाधीश ने लिस्बन, पुर्तगाल की अपील अदालत द्वारा पारित दिनांक 1-बी के आदेश को देखते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दिनांक 1-1 के प्रत्यर्पण आदेश को समाप्त कर दिया गया था।

2. उपरोक्त अपीलों के निपटारे तक, प्रतिवादी-सी. बी. आई. ने आपराधिक विविध दायर किया। अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी बनाम में 2013 के निर्णय और आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए अनुरोध करने वाली याचिकाएं। महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (2011) 11 एस. सी. सी. 214। इन्हीं आवेदनों में, सी. बी. आई. ने अपीलार्थी-अबू सलेम के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों को वापस लेने की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया है। उन्होंने 17.02.2012 दिनांकित स्थगन स्थगन आदेश को हटाने और मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देने के लिए भी प्रार्थना की।

3. सी. बी. आई. द्वारा दिनांक 1 के पूर्व आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए दायर आवेदनों को देखते हुए, वर्तमान आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को उजागर करना उपयोगी है।

4. संक्षिप्त तथ्य

(i) 12.03.1993 पर, बॉम्बे शहर में एक के बाद एक 12 बम विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई, 713 अन्य घायल हो गए और लगभग Rs.27 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद, उक्त घटना के संबंध में बॉम्बे शहर, ठाणे जिले और रायगढ़ जिले के विभिन्न पुलिस थानों में 27 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। जाँच पूरा होने पर, 189 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एकल आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें 44 फरार अभियुक्त (ए. ए.) व्यक्ति शामिल थे।

(ii) जाँच के दौरान, अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। चूंकि अपीलकर्ता फ़रारी था, इसलिए उसे आरोप पत्र में एक भगोड़े अभियुक्त (ए-139) के रूप में दिखाया गया था और 15.09.1993 पर अपीलकर्ता के खिलाफ एक घोषणा जारी की गई थी। एक रेड कॉर्नर नोटिस जिसमें सं. A-103/3-1995 था। अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल द्वारा से भी जारी किया गया।

(iii) नामित न्यायालय ने टाडा की खंड 3 (3) के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का एक सामान्य आरोप तैयार किया और साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.'), शस्त्र अधिनियम, 1959, विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 के तहत विभिन्न आरोप भी बनाए गए।

(iv) उक्त आरोप पत्र में अबू सलेम की विशिष्ट भूमिका यह थी कि उसे अवैध रूप से तस्करी किए गए हथियारों और गोला-बारूद के परिवहन, उनके भंडारण और अन्य साजिशकर्ताओं को वितरित करने का काम सौंपा गया था। कुछ हथियार और विस्फोटक जिनकी तस्करी 09.02.1993 पर भारत में की गई थी, उन्हें भरूच जिले के गांव सन्सरोड ले जाया गया। जनवरी, 1993 के दूसरे सप्ताह में, अबू सलेम ए. के.-56 राइफलें, गोला-बारूद और हथगोले सनस्रोद गाँव से बॉम्बे लाया और उन्हें विभिन्न सह-अभियुक्तों के बीच वितरित किया।

(v) विचारण के समय, नामित न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 299 के प्रयोजन के लिए फरार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(vi) इसमें अपीलकर्ता ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अर्सलान मोहसिन अली के नाम से पुर्तगाल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया। 18.09.2002 पर, अबू सलेम को पुर्तगाली पुलिस ने उक्त रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर लिस्बन में हिरासत में लिया था।

(vii) दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने 9 आपराधिक मामलों (सीबीआई के 3 बी मामले, मुंबई पुलिस के 2 मामले और दिल्ली पुलिस के 4 मामले) में अबू सलेम के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया। यह अनुरोध आतंकवादी बमबारी के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर किया गया था, जिस पर भारत और पुर्तगाल ने हस्ताक्षर किए हैं। इस मांग पर तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे और तथ्यों के आधार पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई./एस. टी. एफ. श्री ओम प्रकाश छतवाल द्वारा शपथ लिए गए एक विस्तृत शपथ पत्र के साथ इसका समर्थन किया गया था।

(viii) 13.12.2002 पर, भारत सरकार ने प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की खंड 3 (1) के तहत इस आशय की अधिसूचना जारी की कि प्रत्यर्पण अधिनियम (अध्याय II के अलावा) के प्रावधान 13.12.2002 से पुर्तगाली गणराज्य पर लागू होंगे।

(ix) 17.12.2002 पर, भारत सरकार ने तत्कालीन उप प्रधान मंत्री द्वारा से पुर्तगाल सरकार को आश्वासन दिया कि यदि अपीलकर्ता को भारत में मुकदमे के लिए प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे न तो मौत की सजा दी जाएगी और न ही 25 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी।

(x) आई. डी. 1 पर, भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी और टाडा की खंड 3 (2) के तहत प्रत्यर्पण को स्वीकार करते हुए मंत्रिस्तरीय आदेश पारित किया गया। हालाँकि, मंत्रिस्तरीय आदेश ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की खंड 25 (1-ए) और (1-बी),

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की खंड 4 और 5, टाडा की खंड 5 और 6 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की खंड 9-बी के तहत अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण को अस्वीकार कर दिया।

(xi) लिस्बन में भारत के राजदूत ने 25.05.2003 पर एक और आश्वासन दिया कि -

(i) अबू सलेम पर उन अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जिनके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है; और

(ii) अबू सलेम को किसी तीसरे देश में फिर से प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।

(xii) भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने आपराधिक साजिश, भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत दंडनीय हत्या, भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के तहत हत्या का प्रयास, भा.दं.सं. सी. की खंड 435 के तहत दंडनीय अपराध, भा.दं.सं. सी. की खंड 436 के तहत दंडनीय आग या विस्फोटक द्वारा शरारत, टाडा की खंड 3 (2) और 3 (3) के तहत दंडनीय अपराध, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की खंड 3 के तहत दंडनीय अपराध और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की खंड 4 के तहत दंडनीय अपराध जैसे विभिन्न अपराधों के संबंध में अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण की अनुमति दी।

(xiii) 10.11.2005 पर, अपीलकर्ता की अभिरक्षा भारतीय अधिकारियों को सौंप दी गई और 11.11.2005 पर, अपीलकर्ता को भारत लाया गया और आर. सी.-1 (एस/93)/सी. बी. एल./एस. टी. एफ., यानी 1993 का बी. बी. सी. नंबर 1 में नामित अदालत, मुंबई के समक्ष पेश किया गया।

(xiv) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 173 (8) के तहत एक पूरक आरोप पत्र 1993 के बी. बी. सी. संख्या 1 में नामित न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के संबंध में दायर किया गया था।

(xv) दिनांक 18.03.2006 के आदेश द्वारा, साजिश के आरोप के अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ मूल आरोप तैयार किए गए थे और उसकी दोषी नहीं होने की याचिका और मुकदमे का दावा दर्ज किया गया था। नामित न्यायालय द्वारा बनाए गए आरोप इस प्रकार हैंः

(i) टाडा की खंड 3 (3) और भा.दं.सं. सी. की खंड 1208 के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश

3(2)(i), (ii), 3 (3), 3 (4), 5 और 6 टाडा की खंडओं के साथ पढ़ा जाता है जिन्हें भा.दं.सं. सी. की खंड 3 और 7 के साथ पढ़ा जाता है जिन्हें शस्त्र अधिनियम, 1959 की खंड 25 (1ए), (1बी) (ए), विस्फोटक अधिनियम, 1884 की खंड 9-बी (1), (बी), (सी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की खंड 3,4 (ए), (बी), 5 और 6 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की खंड 4 के साथ पढ़ा जाता है।

(ii) टाडा की खंड 3 (3);

(iii) टाडा की खंड 5;

(iv) टाडा की खंड 6;

(v) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की खंड 4 (बी);

(vi) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की खंड 5;

(vii) शस्त्र अधिनियम, 1959 की खंड 387 के साथ पठित खंड 25 (1-ए) (1-बी) (ए) और

(viii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की खंड 9-बी

(xvi) अदालत द्वारा बनाए गए अतिरिक्त आरोप (जो अबू सलेम का तर्क है कि प्रत्यर्पण आदेश का उल्लंघन है) टाडा की खंड 5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की खंड 4 (बी) और खंड 5 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 की खंड 9-बी के तहत अपराधों से संबंधित हैं।

(xvii) 31.03.2006 पर, अभियोजन पक्ष ने 2006 की एम. ए. संख्या 144 के रूप में एक आवेदन दायर किया जिसमें अपीलकर्ता के मुकदमे को उसी तरीके से अलग करने की मांग की गई थी जैसे मुस्तफा अहमद दोसा (ए. ए.) के संबंध में नामित न्यायालय द्वारा किया गया था।

(xviii) 12.04.2006 पर, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्पण के प्रासंगिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए 2006 का एम. ए. संख्या 161 होने का एक आवेदन भी दायर किया और अन्य 123 अभियुक्तों के साथ संयुक्त मुकदमे की मांग की, जिनका मुकदमा पूरा होने वाला था।

(xix) दिनांक 13.06.2006 के आदेश के माध्यम से, नामित न्यायालय ने मुकदमे को अलग करने के लिए आवेदन को अनुमति दी और कहा कि मुकदमा 1993 के बीबीसी-1-बी के रूप में जारी रहेगा, जिसमें पहले का संयुक्त मामला 1993 का बीबीसी नंबर 1 था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आश्वासन उस सजा के संबंध में दिए गए थे जिसे अधिरोपित किया जा सकता था न कि उन अपराधों के संबंध में जिनके साथ उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था।

सितंबर, 2006 में, 2006 दाण्डिक अपीलीय सं 990 इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई। उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू करते हुए एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। यह उनकी शिकायत थी कि अधिकारियों ने

बार-बार पुर्तगाल की अदालतों द्वारा पारित आदेशों को दायर करने में विफल रहने और जानबूझकर और जानबूझकर गंभीर संप्रभु आश्वासन का उल्लंघन करके आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। यह उनका स्पष्ट दावा था कि प्रतिवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अपने कपटपूर्ण व्यवहार से राष्ट्र के सम्मान को कम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के तहत स्थापित विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रत्यर्पण अधिनियम की खंड 21 द्वारा प्रत्यर्पण प्राप्त करने और अपीलकर्ता का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। नामित न्यायालय द्वारा किया गया निर्माण स्वीकार्य नहीं है और प्रत्यर्पण डिक्री का उल्लंघन करते हुए नामित न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है और:पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना की। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उस पर उस कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों का आरोप लगाया गया है जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था और उस हद तक आरोप तय करने का आदेश गलत है। अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि मुकदमे को अलग करने का आदेश पूर्वाग्रहपूर्ण है क्योंकि 1993 के बी. बी. सी. नंबर 1 के मुकदमे में दर्ज किए गए इकबालिया बयान और साक्ष्य उसके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अलगाव प्रत्यर्पण डिक्री की भावना के खिलाफ है जो अपीलकर्ता के मुकदमे को बॉम्बे बम विस्फोट मामले तक सीमित करता है।

(xxi) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता ने लिस्बन के अपील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उस पर भारत में 99 के कानून 144 के अनुच्छेद 16 में निहित विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए मुकदमा चलाया जा रहा है।

(xxii) दिनांक 18.05.2007 के आदेश द्वारा, अपील न्यायाधीशालय ने इस आधार पर भारतीय राज्य द्वारा समर्पण के प्रश्न की जांच करने में अपनी असमर्थता

व्यक्त की कि भारतीय राज्य ने कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है जिन पर प्रत्यर्पण दिया गया था और जब उक्त आदेश अपील में किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने दिनांक 13.12.2007 के आदेश द्वारा मामले को अपील न्यायाधीशालय को यह जांचने के लिए भेज दिया कि क्या अपीलकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है।

(xxiii) अपील न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा मामले को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि इस न्यायालय ने 2006 दाण्डिक अपीलीय सं 990 के साथ-साथ 2006 की रिट याचिका संख्या 171 में उपरोक्त कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया।

(xiv) इस न्यायालय ने अबू सलेम (ऊपर) में दिनांक 10.09.2010 के निर्णय और आदेश द्वारा अपील के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया किः-

> "72. हम पहले ही इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि कैसे भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार ने प्रासंगिक अपराधों का उल्लेख करते हुए उच्च स्तर पर एक समझौता किया और अपीलकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया गया। हमने प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की प्रयोज्यता के बारे में भारत सरकार की अधिसूचना पर भी ध्यान दिया है। उक्त अधिसूचना के आलोक में, जो अतिरिक्त शुल्क बनाए गए हैं, वे प्रत्यर्पण अधिनियम की खंड 21 (बी) के प्रावधान के भीतर अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं, वे उन अपराधों से कम हैं जिनके लिए अपीलकर्ता को प्रत्यर्पित किया गया है। यह स्पष्ट

करने के लिए, जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर आरोप लगाया गया है, वे उस अपराध की तुलना में कम सजा के साथ दंडनीय हैं जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है। वर्तमान मामले में दिए गए प्रत्यर्पण में उन तथ्यों को ध्यान में रखा गया था जो उन अपराधों को शामिल करेंगे जिनके साथ अपीलकर्ता पर आरोप लगाया गया है। जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सही बताया गया है, अपराधों का खुलासा पुर्तगाल सरकार के समक्ष रखे गए तथ्यों के उसी समूह द्वारा किया जाता है। हम विद्वान सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुतिकरण और नामित न्यायालय के अंतिम निर्णय से सहमत हैं।"

(XXV) दिनांक 10.09.2010 के फैसले के बाद, लिस्बन की अपील अदालत ने दिनांक 14.09.2011 के फैसले द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि अबू सलेम के प्रत्यर्पण के लिए दिए गए प्राधिकरण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुर्तगाली कानून सं. 144/99 का अनुच्छेद 16 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति पर प्रत्यर्पण के माध्यम से सहयोग के अनुरोध को जन्म देने वाले अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 16 (2) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर सहयोग के अनुरोध में निर्धारित अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि, उक्त दो उप-अनुच्छेदों को उप-अनुच्छेद (5) के साथ पढ़ने की आवश्यकता है जो प्रदान करता है कि उनके अलावा अन्य तथ्यों के संबंध में प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है।

जिसने अनुरोध की नींव रखी। लिस्बन की अपील अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि

"...... पुर्तगाली कानूनी प्रणाली के आलोक में, भारतीय संघ अबू सलेम के प्रत्यर्पण के लिए पुर्तगाली गणराज्य द्वारा लगाई गई सीमाओं पर विचार नहीं कर रहा था, जिसके बारे में वह पूरी तरह से अवगत था।"

(xvi) उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, भारत संघ ने पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायाधीशालय के समक्ष अपील की, लेकिन इसे विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। हालाँकि, पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय के पास on.05.07 है। 2012, भारत संघ द्वारा पसंद की गई अपील का फैसला किया। संक्षिप्तता और सुविधा के लिए, कुछ भाग प्रासंगिक हैं जो नीचे दिए गए हैं:

8. जिस तरह से विशिष्टता के सिद्धांत के उल्लंघन का प्रश्न तैयार किया जाता है, चाहे उसे प्रत्यर्पित व्यक्ति के प्रसव की घटना के रूप में देखा जाए या नहीं, जो अभी भी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के न्यायिक चरण के भीतर आता है, उससे स्वतंत्र रूप से किए गए विचार उस न्यायिक प्रक्रिया पर लागू होते हैं जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया। उस निर्णय के बावजूद जिसकी अपील की संभावना भारत संघ द्वारा ऐसे सिद्धांत के उल्लंघन के अर्थ में विचाराधीन है, जो अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण द्वारा दिए गए प्राधिकरण को समाप्त करता है, न्यायिक निर्णय स्वयं प्रत्यर्पित व्यक्ति के हस्तांतरण को लागू नहीं करता है। विशिष्टता का सिद्धांत जिसके अनुसार प्रत्यर्पित व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है या प्रत्यर्पण के अनुरोध में निर्धारित किए गए तथ्यों के अलावा पुर्तगाली क्षेत्र छोड़ने से पहले उसकी स्वतंत्रता के किसी अन्य प्रतिबंध या निंदा के अधीन नहीं किया जा सकता है (कानून संख्या का अनुच्छेद 16, संख्या 1) एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांत है जिसके माध्यम से अनुरोध किए गए राज्य की संप्रभुता की रक्षा की जाती है और प्रत्यर्पित व्यक्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है (इसके बारे में, ग्रेगरी 8)। रिचर्डसन, "द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी इन

एक्सट्रैक्शन"; और डोमिनिक पोंसुपॉल गलीहार्ट, "ले प्राइस्निपे डे ला स्पेशलिटी एन मैटियर डी एक्सट्रैडिशन"। "रिव्यू इंटरनेशनल डी अधिकार पेनल, 1991, क्रमशः, पृष्ठ 86, और पृष्ठ 201 और निम्नलिखित)। सिद्धांत के उल्लंघन का सवाल, इसलिए, दो अलग-अलग योजनाओं का अनुमान लगाता हैःअनुरोध करने वाले राज्य और अनुरोध किए गए राज्य के बीच संबंध, एक प्रमुख राजनीतिक आधार के साथ; और अनुरोध करने वाले राज्य और प्रत्यर्पित व्यक्ति के बीच संबंधों का, जिसके संबंध में प्रत्यर्पित व्यक्ति यह आश्वासन देता है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति के लिए विशेषज्ञता का सिद्धांत पूर्व के खिलाफ लाभ उठाता है, का विश्लेषण किया जाता है (उपरोक्त कानूनी आधार के बिंदु 2 और ऐसे लेखक, क्रमशः पृष्ठ 86 और निम्नलिखित और पृष्ठ 217 और निम्नलिखित)। जब विचाराधीन वह योजना है जिसमें अनुरोध करने वाले राज्य और प्रत्यर्पित व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं, भले ही प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा लाई गई न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में अनुरोध किए गए राज्य के आंतरिक कानूनी आदेश में विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन निर्धारित किया जाता है, जो वर्तमान रिकॉर्ड में हुआ है, बिना शांति से समझे जाने के माध्यम से इसकी स्वीकार्यता (उपरोक्त कानूनी आधार का cf. point 2) प्रत्यर्पण अनुरोध का अनुरोध करने वाला राज्य इस प्रक्रिया में ऐसे राज्य के संबंध में प्रक्रियात्मक टकराव की स्थिति में नहीं है। प्रक्रियात्मक प्रतिभागी (पक्ष) के रूप में इसकी कोई भूमिका निहित नहीं है जिसके संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके खिलाफ या इसके पक्ष में कोई निर्णय दिया गया था जो प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से इसे पूर्वाग्रहित करता है क्योंकि प्रत्यर्पण की कानूनी प्रकृति हमेशा आपराधिक मामलों में संप्रभु राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग के एक रूप को रोकती है। एक समझ जो सी. आर. पी. के अनुच्छेद 7 नंबर 1 द्वारा भी कायम है, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामलों के संबंध में यह निर्धारित किया जाता है कि पुर्तगाल अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों के बीच राज्यों के बीच समानता के सिद्धांतों और अन्य राज्यों

के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों द्वारा शासित है। विशेषता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए प्रत्यर्पण प्राधिकरण को समाप्त करने वाले कानूनी निर्णय को अन्य बातों के अलावा केवल एक तत्व के रूप में माना जाना चाहिए जिसे अनुरोध किया गया राज्य तब ध्यान में रखता है जब वह अनुरोध करने वाले राज्य के साथ अपने संबंधों की योजना पर राजनीतिक रूप से विचार करता है। इसलिए, यह एक ऐसे निर्णय की पहुंच नहीं रख सकता है जो केवल अपने आप में विशिष्टता के सिद्धांत के उल्लंघन के परिणाम को निर्धारित करता है, जिसे अनुरोध करने वाले राज्य के खिलाफ निर्णय के रूप में लागू किया जाता है, एक ऐसे निर्णय के रूप में जो प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से इसे पूर्वाग्रहित करता है। इससे भी अधिक कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के न्यायिक चरण में जो होता है, जो अनिवार्य रूप से प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी देने के अर्थ में एक प्रशासनिक निर्णय से पहले होता है, उसके विपरीत अभी तक एक प्रमुख राजनीतिक आधार के साथ कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और यह निश्चित है कि विशेषज्ञता के सिद्धांत के उल्लंघन का शामिल राज्यों के बीच संबंधों की योजना पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसा सिद्धांत भी अनुरोध किए गए राज्य की संप्रभुता की स्वायत्त तरीके से रक्षा करता है।

अभी-अभी जो कहा गया है वह सर्वोच्च न्यायाधीशालय के 13.12.2007 के फैसले के अनुरूप है, जो हालांकि आंतरिक कानूनी आदेश के अर्थ में निर्णय लेते हुए विशेषता के सिद्धांत के कथित उल्लंघन पर एक स्थिति लेने के लिए है, यह निष्कर्ष निकालता है कि दिए गए प्राधिकरण की समाप्ति की घोषणा को "बाद में केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा से राजनीतिक शक्ति उदाहरणों को संदर्भित किया जाना चाहिए, ताकि पुर्तगाली राज्य राजनयिक चैनलों द्वारा से उस दृष्टिकोण को अपना सके जिसे वह सबसे सुविधाजनक मानता है" (उपरोक्त रिपोर्ट का सी. एफ. बिंदु 2)। साथ ही 14.09.2011 के लिस्बन अपील न्यायालय के निर्णय के साथ न्यायिक निर्णय जिसकी अपील की गैर-

संभावना मूल्यांकन के तहत नियम से उत्पन्न होती है जिसने इसे पूरा किया। लिस्बन अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय का मूल्यांकन करने और उस पर निर्णय लेने के लिए किए गए दो प्रश्नों के उत्तर में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पुर्तगाली कानूनी प्रणाली के आलोक में, भारत संघ ने कानून सं. 144/99 (पत्रक 587) के अनुच्छेद 16 में निर्धारित विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है और यह कि यद्यपि ऐसा कानून सामान्य शब्दों में प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले राज्य द्वारा विशेषज्ञता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए कोई विशिष्ट परिणाम निर्धारित नहीं करता है, लेकिन यह इस बात को बाधित नहीं करता है कि उल्लंघन के मामले में पुर्तगाली राज्य राजनीतिक राजनयिक माध्यमों द्वारा से प्रतिक्रिया दे सकता है। इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली न्यायिक मामलों द्वारा तैयार किया गया निर्णय प्रासंगिक होगा। इसके अलावा पुर्तगाली राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप करने और मामले से उचित राजनीतिक परिणाम निकालने का अनुरोध करने की संभावना है। वह है:नए अपराधों के लिए मुकदमे को अवैध मानने और अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी के प्रत्यर्पण के लिए दिए गए प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लेने के बावजूद, लिस्बन अपील न्यायालय का निर्णय केवल विशेषज्ञता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए समाप्त होता है। यह अपने आप में अनुरोध करने वाले राज्य को किसी निश्चित कार्य के अभ्यास और प्रत्यर्पित व्यक्ति को वापस करने के लिए बाध्य नहीं करता है और इस प्रकार यह भारत संघ के खिलाफ दिया गया निर्णय नहीं है, एक ऐसा निर्णय जो प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से इसे पूर्वाग्रहित करता है। यह जानने के सवाल के जवाब के परिणामस्वरूप कि पुर्तगाली कानून के आलोक में विशेषज्ञता के सिद्धांत के उल्लंघन का परिणाम क्या है, यह पुर्तगाली न्यायिक मामलों के बजाय पुर्तगाली राज्य पर यह तय करना अनिवार्य होगा कि ऐसा परिणाम क्या होगा, जिसका संबंध दोनों संप्रभु राज्यों के बीच संबंधों की राजनीतिक राजनयिक योजना से होगा।

5. अपीलकर्ता के विद्वान महान्यायवादी सुदीप पासबोला और प्रत्यर्थी-सी. बी. आई. के विद्वान महान्यायवादी श्री जी. ई. वाहनवती।

चर्चाः

6. इस न्यायालय ने अबू सलेम (उपर्युक्त) (2011) 11 एस. सी. सी. 214 में अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए, भारत संघ की ओर से विशेषज्ञता के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जबकि पुर्तगाल के न्यायालयों ने अन्यथा निर्णय लिया है; इस न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय दिया गया कारण यह है कि अपीलकर्ता पर उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था जो उन अपराधों की तुलना में कम प्रकृति के हैं जिनके लिए प्रत्यर्पण दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि पुर्तगाल में इस न्यायालय और न्यायालयों के निर्णयों के अनुपात में मतभेद हैं।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी प्रस्तुत किया कि हालाँकि पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय ने किसी संवैधानिक मुद्दे पर भारत संघ की अपील पर विचार नहीं किया होगा, फिर भी न्यायालय ने कहा है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोध किए गए राज्य को वापस करना है या नहीं, यह कुछ ऐसा मुद्दा है जिसे दोनों देश राजनयिक रूप से तय कर सकते हैं। यह भी बताया गया है कि भारत संघ, राजनयिक मार्गों द्वारा से, वर्तमान मुद्दे पर पुर्तगाल सरकार के संपर्क में है। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, पुर्तगाल महान्यायवादी ने भारत संघ की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उनके पास अपील करने का कोई अधिस्थिति नहीं है क्योंकि यह उनके खिलाफ आदेश नहीं है। एच को हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय के फैसले के अनुसार, अपीलकर्ता-अबू सलेम ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को अभियोजन पक्ष द्वारा कथित उल्लंघन के कारण प्रत्यर्पण आदेश को

रद्द करने का मामला बनाने की कोशिश करते हुए दिनांक 1 का अभ्यावेदन दिया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने लिस्बन की अपील अदालत में 19.09.2012 पर एक याचिका दायर की है जिसमें प्रार्थना की गई है कि पुर्तगाली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए पुर्तगाल को उसके हस्तांतरण के लिए कदम उठाने के लिए पुर्तगाल सरकार को निर्देश दिए जा सकते हैं।

8. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ता के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र में उल्लिखित आठ आरोपों में से, उपरोक्त धारा संख्या (iii) से (viii) में उल्लिखित आरोपों को पुर्तगाली न्यायालय द्वारा "अतिरिक्त आरोप" कहा गया है, जिसके कारण यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा, जिस तकनीकीता पर अपीलकर्ता ने भारत के साथ-साथ पुर्तगाल में भी विभिन्न आपत्तियां/मुकदमे/अभ्यावेदन उठाए हैं, वह ऊपर दिए गए एस सं (iii) से (viii) के आरोपों के संबंध में है। पुर्तगाल सरकार को दी गई पूर्व प्रतिबद्धता को देखते हुए और न्यायाधीशालयों की समिति के साथ-साथ न्यायाधीश के हित को देखते हुए, प्रतिवादी-सी. बी. आई. उपरोक्त आरोप, यानी एस सं (iii) से (viii) तक के आरोप को वापस लेना चाहता है। विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह कहा गया है कि यदि इस न्यायालय द्वारा वर्तमान आवेदनों की अनुमति दी जाती है और उपरोक्त को देखते हुए महान्यायवादी के मुकदमे पर रोक हटा दी जाती है तो महान्यायवादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. दूसरी ओर, अपीलार्थी-अबू सलेम के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी का वर्तमान आवेदन 2006 दाण्डिक अपीलीय सं 990 और रिट याचिका (सी. आर. एल.) में दिए गए 10.09.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए प्रार्थना कर रहा है। 2006 का सं. 171 परेशान करने वाला है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता

द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रत्यर्पण का आदेश स्वयं अलग कर दिया गया है और अब वैध और अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अतिरिक्त शुल्कों को वापस लेने का कोई प्रभाव नहीं होगा और अपीलकर्ता पर भारत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गयाः- "सबसे पहले, क्या यह न्यायालय प्रतिवादी द्वारा उठाए गए आधारों के तहत (2011) 11 धारा 214 में रिपोर्ट किए गए अबू सलेम (उपरोक्त) दिनांक 10.09.2010 में दिए गए निर्णय को संशोधित कर सकता है।

"दूसरा, क्या दिनांकित प्रत्यर्पण का आदेश रद्द/रद्द किया गया है जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है।"

11. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायाधीशालय को अपने पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार करने, संशोधित करने और संशोधित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है क्योंकि कानून को न्यायाधीश के सामने झुकना पड़ता है। निश्चित रूप से, इस न्यायाधीशालय को त्रुटि को सुधारने से कुछ भी नहीं रोक सकता है यदि वह पाता कि संशोधन याचिका में बताई गई त्रुटि गलती से हुई थी और पहले का निर्णय गलत धारणा के लिए पारित नहीं किया गया होता जो वास्तव में मौजूद नहीं था और इसके अपराध के परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता हुई थी।

12. दिए गए मामले में, एकमात्र आधार जिस पर प्रतिवादी/सी. बी. आई. संशोधन चाहता है, वह है विशिष्टता के सिद्धांत के उल्लंघन के संबंध में अलग-अलग विचारों से उत्पन्न स्थिति का सामंजस्य स्थापित करना। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालयों के समुदाय के हित में, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

एकजुट लड़ाई के लिए, भारत सरकार राजनयिक माध्यमों द्वारा आगे के प्रयास कर रही है। नतीजतन, प्रत्यर्थी का विचार है कि अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए अतिरिक्त आरोप, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 10.09.2010 के आदेश में वैध ठहराया गया था, राजनयिक वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए बाधा के रूप में आ सकते हैं। आज की तारीख में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय द्वारा दिए गए विशेषज्ञता के सिद्धांत के उल्लंघन के संबंध में दो अलग-अलग विचार मौजूद हैं। भारत संघ के लिए उपलब्ध विकल्प या तो अलग-अलग दृष्टिकोण को निपटाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच से संपर्क करना है या राजनयिक चैनलों के माध्यम से वैकल्पिक सुलह करना है। अभियुक्त/अपीलकर्ता के अभियोजन में दो दशकों की देरी को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी का विचार है कि अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने से प्रक्रिया में कमी आएगी। इसलिए, प्रतिवादी इस संशोधन याचिका के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को वापस लेने की अनुमति मांगता है। जबकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष केवल अपीलकर्ता के मुकदमे के अंतहीन स्थगन से बचने के लिए दायर की गई है।

13. इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले प्रत्यर्पण की अवधारणा के पीछे के कारण को समझना महत्वपूर्ण है। प्रत्यर्पण, प्रथा के पूरे इतिहास में, कई प्रक्रियाओं से युक्त एक प्रणाली बनी हुई है, जिसके तहत एक संप्रभु दूसरे संप्रभु को आत्मसमर्पण कर देता है, एक व्यक्ति जिसे आरोपी अपराधी या भगोड़े अपराधी के रूप में मांगा जाता है। अनुरोध करने वाले संप्रभु को व्यक्तियों का यह वितरण आमतौर पर संधियों या द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित होता है, लेकिन कभी-कभी यह संप्रभुों के बीच शिष्टाचार और सद्भावना के मामले के रूप में पारस्परिकता और सौहार्द से भी होता है जैसा कि इस

मामले में होता है। इसलिए, 'विश्व सार्वजनिक व्यवस्था' आवर्ती विषय है जिसके आधार पर राज्यों द्वारा प्रत्यर्पण का अभ्यास किया जाता है।

14. प्रत्यर्थी के इस कथन पर ध्यान दें हुए कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता को भारत प्रत्यर्पित किया गया था, वे अपीलकर्ता को अधिकतम सजा देने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं और इसलिए यदि संशोधन के लिए वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है तो कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा, हमारा विचार है कि मौजूदा विशिष्ट परिस्थितियों में वर्तमान संशोधन याचिका को अनुमति देना किसी भी पक्ष के लिए हानिकारक नहीं होगा। हालाँकि, यह स्पष्ट करना उचित है कि प्रतिवादी द्वारा दायर संशोधन याचिका को अनुमति देकर, यह नहीं माना जा सकता है कि यह न्यायालय पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय के फैसले के आलोक में फैसले की समीक्षा कर रहा है। भारत और पुर्तगाल दोनों कुशल शुष्क स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली वाले दो संप्रभु राज्य हैं। परिणामस्वरूप, स्पष्ट शब्दों में, पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इसका केवल प्रेरक मूल्य है।

15. परिणामस्वरूप, यद्यपि इस महान्यायवादी के हित में और विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिए गए इस कथन पर कि मामले को राजनयिक माध्यमों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, सी. बी. आई. के पक्ष में निर्णय दिया है, हम प्रत्यर्थी सी. बी. आई. को संशोधन याचिका की अनुमति देते हुए उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लिखित आरोप (iii) द्वारा (viii) को वापस लेने की अनुमति देते हैं। विद्वान महान्यायवादी ने इस न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि वे महान्यायवादी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में लंबित अन्य आरोपों को भी वापस लेने की प्रक्रिया में हैं, जिनके प्रत्यर्पण आदेश का उल्लंघन करने का दावा किया जाता है और इन्हें एतद्द्वारा दर्ज किया जाता है।

16. फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधन याचिका की अनुमति केवल अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने की सीमा तक ही दी जाती है। हालाँकि, विशिष्टता के सिद्धांत की व्याख्या के संबंध में विवादित निर्णय में दिया गया विश्लेषण और तर्क अभी भी अच्छा है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

17. जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है; क्या अपीलार्थियों द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार दिनांकित प्रत्यर्पण का आदेश रद्द/रद्द कर दिया गया है, प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुर्तगाल के न्यायालयों के निर्णय में स्वयं अपीलकर्ता को पुर्तगाल को वापस करने के लिए भारत संघ को कोई निर्देश नहीं है जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा उत्तेजित किया जा रहा है। पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय ने स्पष्ट रूप द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि पुर्तगाली कानून विशिष्टता के सिद्धांत के उल्लंघन के लिए किसी विशिष्ट परिणाम का प्रावधान नहीं करता है और उनके निष्कर्षों को भारत संघ को अपीलकर्ता को पुर्तगाल वापस करने के निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह केवल पुर्तगाल सरकार के लिए एक कानूनी आधार के रूप में काम करेगा, यदि वह राजनीतिक या राजनयिक माध्यमों द्वारा अपीलकर्ता की पुर्तगाल वापसी की मांग करने का विकल्प चुनती है, जो विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार आज तक नहीं किया गया है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि 28.03.2003 दिनांकित प्रत्यर्पण का आदेश अभी भी कानून की नजर में मान्य और प्रभावी है। तदनुसार, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम आपराधिक विविध को अनुमति देते हैं। 2006 दाण्डिक अपीलीय सं 990 और रिट याचिका (सीआरएल) में दिए गए हमारे आदेश दिनांक 10.09.2010 में संशोधन के लिए 2013 की याचिका संख्या 3301-3302

2006 का सं. 171 और प्रत्यर्थी-सी. बी. आई. को आरोप वापस लेने की अनुमति देना। आरोप संख्या (iii) से (viii) जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। नतीजतन, हम 17.02.2012 दिनांकित स्थगन स्थगन आदेश को खाली कर देते हैं और मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने अन्य आरोपों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है और दोनों पक्ष अपना-अपना रुख रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

19. आपराधिक विविध मामले में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए। 2013 की याचिका संख्या 3301-3302, उपरोक्त अपीलों में आगे किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अपीलार्थी-अबू सलेम द्वारा दायर 2012 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 415-416। इन अपीलों का तदनुसार आपराधिक विविध मामले में पारित आदेश के संदर्भ में निपटारा किया जाता है। 2013 की याचिका संख्या 3301-3302। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अभियोग के लिए आवेदन में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

एफ. आर. पी

अपील और सी. आर. एल. विविध याचिकाओं का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।